



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-20] रुड़की, शनिवार, दिनांक 02 फरवरी, 2019 ई0 (माघ 13, 1940 शक सम्वत्) [संख्या-05

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य ...	—	3075
भाग 1-विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	47-56	1500
भाग 1-क-नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	47-65	1500
भाग 2-आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...	—	975
भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 6-बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटीयों की रिपोर्ट ...	—	975
भाग 7-इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...	—	975
भाग 8-सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	—	975
स्टोर्स पर्चेज-स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

सामान्य प्रशासन विभाग

संख्या 91/XXXI(15)G/-47 (सा0)/2018-19

दिनांक 23 जनवरी, 2019 ई0

विज्ञप्ति/ज्ञाप/सार्वजनिक सूचना

एतद्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि "श्रीमती अनुप भाकरी पत्नी श्री राजीव स्वरूप नि0-बी-15 टिहरी हाउस, राजपुर रोड़, देहरादून ने अपना नाम श्रीमती अनुप भाकरी से परिवर्तित कर डॉ0 (श्रीमती) अनु भाकरी स्वरूप कर लिया गया है"।

अतः भविष्य में श्रीमती अनुप भाकरी को परिवर्तित नाम डॉ0 (श्रीमती) अनु भाकरी स्वरूप से ही जाना जायेगा।

राधा रतूड़ी,

अपर मुख्य सचिव।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें अनुभाग-1

विज्ञप्ति/पदोन्नति

21 दिसम्बर, 2018 ई0

संख्या 1628/XIX-1/18-141/2006-एतद्वारा डा0 एम0एस0विसेन, उपायुक्त, को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त आयुक्त (खाद्य) वेतनमान ₹ 15600-39100 ग्रेड वेतन ₹ 7600 (7 वें वेतन आयोग में वेतन मैट्रिक्स (लेविल 12) ₹ 78800-209200) के पद पर अस्थाई रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2-पदोन्नति के फलस्वरूप डा0 एम0एस0विसेन को संयुक्त आयुक्त (खाद्य) के पद पर 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3-प्रश्नगत पदोन्नति उत्तराखण्ड राज्य हेतु होने वाले अन्तिम आवंटन के अधीन होगी। भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शी समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उत्तर प्रदेश के अन्य कार्मिक उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं, तो तदपरिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में, इस आदेश को, तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथावश्यक परिवर्तित/प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

विज्ञप्ति/पदोन्नति

21 दिसम्बर, 2018 ई0

संख्या 1629/XIX-1/18-141/2006-एतद्वारा श्री विपिन कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी, देहरादून को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उपायुक्त (खाद्य) वेतनमान ₹ 15600-39100 ग्रेड वेतन ₹ 6600 (7 वें वेतन आयोग में वेतन मैट्रिक्स (लेविल 11) ₹ 67700-208700) के पद पर अस्थाई रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2-पदोन्नति के फलस्वरूप श्री विपिन कुमार को उपायुक्त (खाद्य) के पद पर 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3-उपायुक्त (खाद्य) के पद पर श्री विपिन कुमार की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे। अतः श्री विपिन कुमार द्वारा जिला पूर्ति अधिकारी, देहरादून का कार्य पूर्ववत् सम्पादित किया जायेगा और योगदान आख्या की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

4-प्रश्नगत पदोन्नति उत्तराखण्ड राज्य हेतु होने वाले अन्तिम आवंटन के अधीन होगी। भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शी समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उत्तर प्रदेश के अन्य कार्मिक उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं, तो तदपरिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में, इस आदेश को, तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथावश्यक परिवर्तित/प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

विज्ञप्ति/पदोन्नति

21 दिसम्बर, 2018 ई०

संख्या 1630/XIX-1/18-16 खाद्य/2012-एतद्वारा श्री जी०एस०रावत, सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, कुमायूँ सम्भाग, हल्द्वानी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उप नियंत्रक (विधिक माप विज्ञान) वेतनमान ₹ 15600-39100 ग्रेड वेतन ₹ 6600 (7 वें वेतन आयोग में वेतन मैट्रिक्स (लेविल 11) ₹ 67700-208700) के पद पर अस्थाई रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2-पदोन्नति के फलस्वरूप श्री जी०एस०रावत को उप नियंत्रक (विधिक माप विज्ञान) के पद पर 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3-उप नियंत्रक (विधिक माप विज्ञान) के पद पर श्री जी०एस०रावत की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे। अतः श्री जी०एस०रावत द्वारा उप नियंत्रक विधिक माप विज्ञान, कुमायूँ सम्भाग, हल्द्वानी का कार्य सम्पादित किया जायेगा और योगदान आख्या की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

4-प्रश्नगत पदोन्नति उत्तराखण्ड राज्य हेतु होने वाले अन्तिम आवंटन के अधीन होगी। भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शी समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उत्तर प्रदेश के अन्य कार्मिक उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं, तो तदपरिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में, इस आदेश को, तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथावश्यक परिवर्तित/प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

विज्ञप्ति/पदोन्नति

21 दिसम्बर, 2018 ई०

संख्या 1631/XIX-1/18-16 खाद्य/2012-एतद्वारा श्री खुशाल सिंह रावत, वरिष्ठ निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान, कुमायूँ सम्भाग, हल्द्वानी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक नियंत्रक (विधिक माप विज्ञान) वेतनमान ₹ 15600-39100 ग्रेड वेतन ₹ 5400 (7 वें वेतन आयोग में वेतन मैट्रिक्स (लेविल 10) ₹ 56100-177500) के पद पर अस्थाई रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2-पदोन्नति के फलस्वरूप श्री खुशाल सिंह रावत को सहायक नियंत्रक (विधिक माप विज्ञान) के पद पर 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3-सहायक नियंत्रक (विधिक माप विज्ञान) के पद पर श्री खुशाल सिंह रावत की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे। अतः श्री खुशाल सिंह रावत द्वारा सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान, कुमायूँ सम्भाग, हल्द्वानी का कार्य सम्पादित किया जायेगा और योगदान आख्या की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

4-प्रश्नगत पदोन्नति उत्तराखण्ड राज्य हेतु होने वाले अन्तिम आवंटन के अधीन होगी। भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शी समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उत्तर प्रदेश के अन्य कार्मिक उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं, तो तदपरिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में, इस आदेश को, तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथावश्यक परिवर्तित/प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

आज्ञा से,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव।

गृह अनुभाग-8

अधिसूचना

19 दिसम्बर, 2018 ई0

संख्या 964/XX(8)2018-11(02)2016-राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2, वर्ष 1974) की धारा 2(ध) सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, वर्ष 1897) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा इस विषय पर विद्यमान सभी शासनादेशों/अधिसूचनाओं, जहाँ तक वे जिला देहरादून के पुलिस थाना ऋषिकेश/पुलिस थाना डोईवाला की नियमित क्षेत्राधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों/ग्रामों से सम्बन्धित हैं, का आंशिक रूप से संशोधन करते हुए परिशिष्ट में दी गई सूची के क्षेत्रों/ग्रामों को पुलिस थाना रानीपोखरी में सम्मिलित किये जाने एवं तदनुसार पुलिस थाना रानीपोखरी को अधिसूचित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. राज्यपाल, यह भी निर्देश देते हैं कि परिशिष्ट में उल्लिखित क्षेत्र/ग्राम जिला देहरादून के पुलिस थाना रानीपोखरी, के नियमित अधिकारिता क्षेत्र में सम्मिलित होंगे तथा देहरादून के पुलिस थाना ऋषिकेश/पुलिस थाना डोईवाला के नियमित अधिकारिता क्षेत्र से निकाल दिए जायेंगे।

परिशिष्ट

जिला देहरादून के अन्तर्गत पुलिस थाना ऋषिकेश/पुलिस थाना डोईवाला के नियमित अधिकारिता क्षेत्र से निकालते हुए, पुलिस थाना रानीपोखरी में सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्रों/ग्रामों की सूची:-

क्र0सं0	पुलिस थाना रानीपोखरी के नियमित क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत क्षेत्र/ग्रामों की सूची
1	2
1.	रामनगर डाण्डा
2.	कन्डोगल
3.	कुडियाल
4.	घण्डोल
5.	कटकूर कलां
6.	कटकूर खुर्द
7.	कुठार
8.	गढ़-तगोली
9.	धारकोट
10.	बडेरना कलां
11.	बडेरना खुर्द
12.	बडेरना मांझला
13.	लटवाकोट
14.	सिम्याद
15.	बैरागढ़
16.	रखववाल
17.	विशानबढ़

1	2
18.	धम्भूवाला
19.	चित्तोर
20.	प्लेड
21.	घाईसैण
22.	थानो
23.	कखनावा मयचक
24.	घडोलगाँव
25.	कोटि मयचक

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 964/XX(8)2018-11(02)016**, dated December 19, 2018 for general information.

NOTIFICATION

December 19, 2018

No. 964/XX(8)2018-11(02)016—In exercise of the powers conferred by Section 2(s) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act No. 10 of 1897) and by partially amending the all existing Government Orders/Notifications on the subject as far as they are related to the areas/villages included within the regular jurisdiction of the Police Station Rishikesh and Police Station Doiwala of the District Dehradun, the Governor is pleased to allow, to include the areas/villages of the list as given in Appendix in the Police Station Ranipokhari and to notify the Police Station Ranipokhari accordingly.

The Governor also directs that the areas/villages as mentioned in the Appendix shall be included in the regular jurisdiction of the Police Station Ranipokhari of District Dehradun and shall be excluded from the regular jurisdiction of Police Station Rishikesh and Police Station Doiwala of District Dehradun.

Appendix

List of the areas/villages to be included in the jurisdiction of the Police Station Ranipokhari of District Dehradun, by excluding from the jurisdiction of Police Station Rishikesh and Police Station Doiwala, of District Dehradun :--

S. No.	List of Areas/Villages under the of regular jurisdiction of the Police Station Ranipokhari
1	2
1.	Ramanagar Danda
2.	Kandogal
3.	Kudiyal
4.	Ghandol
5.	Katkoor Kalan
6.	Katkoor Khurd

1	2
7.	Khutaar
8.	Garh-tagoli
9.	Dharkot
10.	Baderna Kalan
11.	Baderna Khrud
12.	Baderna Manjhala
13.	Latvakot
14.	Simmiyaad
15.	Bairagadh
16.	Rakhawaal
17.	Bishanbadh
18.	Dhammuwala
19.	Chittoor
20.	Plade
21.	Ghaisain
22.	Thano
23.	Khanava Maychak
24.	Ghandolgaon
25.	Kotimaychak

अधिसूचना

19 दिसम्बर, 2018 ई0

संख्या 965/XX(8)2018-11(02)2016-राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2, वर्ष 1974) की धारा 2(घ) सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, वर्ष 1897) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा इस विषय पर विद्यमान सभी शासनादेशों/अधिसूचनाओं, जहाँ तक वे जिला देहरादून के पुलिस थाना कोतवाली देहरादून की नियमित क्षेत्राधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों/ग्रामों से सम्बन्धित हैं, का आंशिक रूप से संशोधन करते हुए परिशिष्ट में दी गई सूची के क्षेत्र/ग्राम को पुलिस थाना पटेलनगर में सम्मिलित किये जाने एवं तदनुसार पुलिस थाना पटेलनगर को अधिसूचित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. राज्यपाल, यह भी निर्देश देते हैं कि परिशिष्ट में उल्लिखित क्षेत्र/ग्राम जिला देहरादून के पुलिस थाना पटेलनगर के नियमित अधिकारिता क्षेत्र में सम्मिलित होंगे तथा पुलिस थाना कोतवाली देहरादून के नियमित अधिकारिता क्षेत्र से निकाल दिए जायेंगे।

परिशिष्ट

जिला देहरादून के अन्तर्गत पुलिस थाना कोतवाली देहरादून के नियमित अधिकारिता क्षेत्र से निकालते हुए, पुलिस थाना पटेलनगर में सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्रों/ग्रामों की सूची:-

क्र0सं0	पुलिस थाना पटेलनगर के नियमित क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत क्षेत्र/ग्रामों की सूची
1.	15/5 सहारनपुर रोड़ से 1/6 मातावाला बाग तक

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 965/XX(8)2018-11(02)016, dated December 19, 2018 for general information.

NOTIFICATION

December 19, 2018

No. 965/XX(8)2018-11(02)016—In exercise of the powers conferred by Section 2(s) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act No. 10 of 1897) and by partially amending the all existing Government Orders/Notifications on the subject as far as they are related to the areas/villages included within the regular jurisdiction of the Police Station Kotwali of District Dehradun, the Governor is pleased to allow, to include the areas/villages of the list as given in Appendix in the Police Station Patel Nagar and to notify the Police Station Patel Nagar accordingly.

The Governor also directs that the areas/villages as mentioned in the Appendix shall be included in the regular jurisdiction of the Police Station Patel Nagar of District Dehradun and shall be excluded from the regular jurisdiction of Police Station Kotwali of District Dehradun.

Appendix

List of the areas/villages to be included in the jurisdiction of the Police Station Patel Nagar of District Dehradun, by excluding from the jurisdiction of Police Station Kotwali of the District Dehradun :--

S. No.	List of Areas/Villages under the of regular jurisdiction of the Police Station Patel Nagar
1.	From 15/5 Saharanpur road to 1/6 Mata Wala Baag

अधिसूचना

19 दिसम्बर, 2018 ई०

संख्या 966/XX(8)2018-11(02)2016—राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2, वर्ष 1974) की धारा 2(घ) सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, वर्ष 1897) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा इस विषय पर विद्यमान सभी शासनादेशों/अधिसूचनाओं, जहाँ तक वे जिला देहरादून के पुलिस थाना पटेलनगर की नियमित क्षेत्राधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों/ग्रामों से सम्बन्धित हैं, का आंशिक रूप से संशोधन करते हुए परिशिष्ट में दी गई सूची के क्षेत्रों/ग्रामों को पुलिस थाना बसन्त विहार में सम्मिलित किये जाने एवं तदनुसार पुलिस थाना बसन्त विहार को अधिसूचित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. राज्यपाल, यह भी निर्देश देते हैं कि परिशिष्ट में उल्लिखित क्षेत्र/ग्राम जिला देहरादून के पुलिस थाना बसन्त विहार देहरादून के नियमित अधिकारिता क्षेत्र में सम्मिलित होंगे तथा देहरादून के पुलिस थाना पटेलनगर के अधिकारिता क्षेत्र से निकाल दिये जायेंगे।

परिशिष्ट

जिला देहरादून के अन्तर्गत पुलिस थाना पटेलनगर के नियमित अधिकारिता क्षेत्र से निकालते हुए, पुलिस थाना बसन्त विहार में सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्रों/ग्रामों की सूची:-

क्र०सं०	पुलिस थाना बसन्त विहार के नियमित क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत क्षेत्र/ग्राम की सूची
1.	साँईलोक कालोनी (समस्त पश्चिम क्षेत्र)

आज्ञा से,

नितेश कुमार झा,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 966/XX(8)2018-11(02)016**, dated December 19, 2018 for general information.

NOTIFICATION

December 19, 2018

No. 966/XX(8)2018-11(02)016—In exercise of the powers conferred by Section 2(s) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act No. 10 of 1897) and by partially amending the all existing Government Orders/Notifications on the subject as far as they are related to the areas/villages included within the regular jurisdiction of the Police Station Patel Nagar of District Dehradun, the Governor is pleased to allow, to include the areas/villages of the list as given in Appendix in the Police Station Basant Vihar and to notify the Police Station Basant Vihar accordingly.

The Governor also directs that the areas/villages as mentioned in the Appendix shall be included in the regular jurisdiction of the Police Station Basant Vihar of District Dehradun and shall be excluded from the regular jurisdiction of Police Station Patel Nagar of District Dehradun.

Appendix

List of the areas/villages to be included in the jurisdiction of the Police Station Basant Vihar of District Dehradun, by excluding from the jurisdiction of Police Station Patel Nagar of District Dehradun :--

S. No.	List of Areas/Village under the jurisdiction of the Police Station Basant Vihar
1.	Sailok Colony (All western area)

By Order,

NITESH KUMAR JHA,
Secretary.

गृह अनुभाग-1

विज्ञप्ति/पदोन्नति

26 दिसम्बर, 2018 ई०

संख्या 1040/XX(1)-2018-3(12)2014-उत्तराखण्ड प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग के पुलिस उपाधीक्षक, कनिष्ठ वेतनमान (वेतन मैट्रिक्स में लेवल-10) के पद पर प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत चयन वर्ष 2018-19 की रिक्तियों के सापेक्ष उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार की संस्तुति के क्रम में निम्नलिखित स्थायी पुलिस निरीक्षकों को पुलिस उपाधीक्षक, कनिष्ठ वेतनमान (वेतन मैट्रिक्स में लेवल-10) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०सं०	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)
1.	हरीश चन्द्र भट्ट
2.	पुरुषोत्तम दत्त जोशी
3.	कमल सिंह पंवार
4.	नरेश चन्द्र

1	2
5.	मुकेश कुमार पुनेठा
6.	बृजभूषण दत्त जुयाल
7.	अरविन्द सिंह रावत
8.	अमर सिंह गुंज्याल
9.	चन्द्रशेखर काण्डपाल
10.	धीरेन्द्र सिंह रावत
11.	कुन्दन सिंह देव

2-उक्त स्थायी पुलिस निरीक्षकों की पदोन्नति पुलिस उपाधीक्षक, कनिष्ठ वेतनमान के पद पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. उक्तानुसार पदोन्नत किये जाने वाले कार्मिकों को उनके कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा काल पर रखा जायेगा जैसा कि उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली, 2009 के नियम-24 में प्रावधान है।
2. उक्तवत् पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों की ज्येष्ठता उक्त सेवा में पूर्व से नियुक्त किये गये तथा नियुक्त किये जाने वाले अन्य अभ्यर्थियों के साथ कालान्तर में सुसंगत नियमों के अनुसार निर्गत की जायेगी।
3. पदोन्नति के उपरान्त भी पदोन्नत किये जा रहे कार्मिकों के सम्बन्ध में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य भविष्य में प्रकाश में आता है तो ऐसे कार्मिकों की पदोन्नति तात्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी।

विज्ञप्ति/पदोन्नति

26 दिसम्बर, 2018 ई0

संख्या 1041/XX-1-2018-2(1)2009-भारतीय पुलिस सेवा (उत्तराखण्ड संवर्ग) के निम्नलिखित अधिकारी को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-4 में अंकित तिथि से वरिष्ठ समय वेतनमान, वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 के पद पर प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	आवंटन वर्ष	अनुमन्यता की तिथि
1	2	3	4
1	सुश्री रचिता	2015	01जनवरी, 2019

आज्ञा से,

नितेश कुमार झा,
सचिव।

नियोजन अनुभाग-1

विज्ञप्ति/पदोन्नति

12 दिसम्बर, 2018 ई0

संख्या 277/XXVI/एक(12)/2008-राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ शोध अधिकारियों को विभागीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर उनके नियमित चयनोपरान्त संयुक्त निदेशक के पद पर वेतनमान ₹ 78800-209200 (लेबल-12) पर अस्थाई रूप से पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. श्री दिनेश चन्द्र वर्मा
2. श्री राजकुमार
3. श्री दीवानी राम

2-उक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अपने नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

3-उक्त अधिकारियों को नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप 02 वर्ष की परीवीक्षा पर रखा जाता है।

आज्ञा से,

जी0बी0 ओली,
अपर सचिव।

पंचायतीराज अनुभाग-1

अधिसूचना

03 जनवरी, 2019 ई0

संख्या 12/XII(1)-2019-84(01)/2006-रिट पिटीशन संख्या 1193/2014(एम0एस0) श्रीमती राजरानी बनाम मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-09-2018 के अनुपालन में, पंचायतीराज एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 767/XII/2005/86(34)2005, दिनांक 10 अक्टूबर, 2005 के प्रस्तर-1 की तालिका 5 द्वारा ग्राम स्तर पर (ग्राम पंचायत कार्यालय) "ग्राम प्रधान" को लोक सूचना अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी को अपीलीय अधिकारी नामित किए जाने सम्बन्धी उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायतीराज विभाग से सम्बन्धित कार्य हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी, नामित किया जाता है।

हरि चन्द्र सेमवाल,
अपर सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 05 हिन्दी गजट/81-भाग 1-2019 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 02 फरवरी, 2019 ई0 (माघ 13, 1940 शक सम्वत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

January 03, 2019

No. 01/UHC/Admin.(A)/2016--Sri Gurpreet Singh, Joint Principal Private Secretary of the Court is hereby posted as Principal Private Secretary (Ex-cadre Post) in the pay scale of ₹ 131100-216600 (Level 13-A) in the establishment of the High Court of Uttarakhand, Nainital with effect from the date of his taking over charge.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

PRADEEP PANT,

Registrar General.

NOTIFICATION

January 03, 2019

No. 02/XIV-a/30/Admin.A/2010--Sri Dharam Singh, the then Judge, Family Court Nainital, presently posted as 6th Additional District & Sessions Judge, Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 15 days w.e.f. 15.11.2018 to 29.11.2018.

NOTIFICATION

January 03, 2019

No. 03/XIV/18/Admin.A/2008--Sri Vivek Dwivedi, 3rd Additional District & Sessions Judge, Rudrapur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned Medical leave for 07 days w.e.f. 03.12.2018 to 09.12.2018.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

January 03, 2019

No. 04/UHC/Admin.A/2019--In exercise of powers conferred by Sub section (2) of Section 19 of the Bengal, Agra, and Assam Civil Courts Act, 1887 (Act No. XII of 1887) [also applicable to the State of Uttarakhand] read with Government of Uttarakhand Notification No. 420-Ek (1)/XXXVI (1)/Nyay Anubhag/2005 dated 07.11.2005, the High Court is pleased to direct that the following 15 Civil Judges (Jr. Div.), posted in the State of Uttarakhand, Shall have jurisdiction to try Civil Suits of pecuniary value not exceeding ₹ 1.00 Lac.

S. No.	Name
1.	Sri Bhupendra Singh Shah
2.	Ms. Minakshi Dubey
3.	Ms. Bhawna Pandey
4.	Sri Vivek Singh Rana
5.	Ms. Shikha Bhandari
6.	Sri Rizwan Ansari
7.	Ms. Kanchan Chaudhary
8.	Ms. Shalini Dadar
9.	Ms. Nisha Devi
10.	Ms. Shivani Nahar
11.	Sri Rohit Joshi
12.	Sri Shambhu Nath Singh Sethwal
13.	Sri Laval Kumar Verma
14.	Sri Kuldeep Narayan
15.	Sri Anil Kumar Kori

By Order of the Court,

Sd/-

PRADEEP PANT,

Registrar General.

NOTIFICATION

January 03, 2019

No. 05/XIV-a/51/Admin.A/2015--Ms. Manju Devi, Civil Judge (Jr. Div.), Gopeshwar, District Chamoli is hereby sanctioned Medical leave for 22 days w.e.f. 09.08.2018 to 30.08.2018.

NOTIFICATION

January 03, 2019

No. 06/XIV-a/40/Admin.A/2012--Sri Abhishek Kumar Srivastava, Civil Judge (Sr. Div.), Almora is hereby sanctioned earned leave for 29 days w.e.f. 24.11.2018 to 22.12.2018 with permission to suffix 23.12.2018 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

January 03, 2019

No. 07/XIV-a/51/Admin.A/2012--Ms. Anita Kumari, Civil Judge (Jr. Div.), Roorkee, District Hardwar, is hereby sanctioned earned leave for 18 days w.e.f. 28.11.2018 to 15.12.2018 with permission to suffix 16.12.2018 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

January 03, 2019

No. 08/XIV-a/37/Admin.A/2016--Ms. Soniya, Civil Judge (Jr. Div.), New Tehri is hereby sanctioned earned leave for 15 days w.e.f. 08.11.2018 to 22.11.2018 with permission to prefix 04.11.2018 to 07.11.2018 as holidays and suffix 23.11.2018 as Public holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY HIGH COURT CAMPUS,
NAINITAL

NOTIFICATION

December 13th, 2018

No. 1380/III-B-2009-10/SLSA/2018--In exercise of the powers conferred under Section 22B of the Legal Services Authorities Act, 1987, provisions of the Permanent Lok Adalat (Other Terms and Conditions of Appointment of Chairman and Other Persons) Rules, 2003 and pursuant to the recommendation of the Hon'ble High Court of Uttarakhand vide Letter No. 5838/UHC/XIII/f-1/Admin.A/2018, dated 11th December, 2018 the Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital hereby appoints the following Judicial Officers as Chairman, Permanent Lok Adalats, as additional Charge to their present duties :--

December 13th, 2018

No. 1380/III(2)-B-2009-10/SLSA/2018--Sri Brijendra Singh, Judge, Family Court, Nainital is appointed as Chairman, Permanent Lok Adalat, Nainital, as additional charge to his present duties.

December 13th, 2018

No. 1380/III(3)-B-2009-10/SLSA/2018--Ms. Reena Negi, 4th Additional District & Sessions Judge, Haridwar is appointed as Chairman, Permanent Lok Adalat, Haridwar, as additional charge to her present duties.

Note: This order will come into force with immediate effect.

By Order of the Hon'ble Executive Chairman,

Sd/-

PRASHANT JOSHI,

Member Secretary.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

CHARGE CERTIFICATE

(Handing Over)

January 02, 2019

No. 16/Admn. (A) UHC/--CERTIFIED that the Office of the Principal Private Secretary to Hon'ble the Chief Justice, High Court of Uttarakhand, Nainital was handed over on superannuation, as herein denoted in the afternoon of 31st December, 2018.

P. S. MANDRAWAL,

Relieved Officer.

Counter-signed

(PRADEEP PANT)

Registrar General

High Court of Uttarakhand, Nainital.

CHARGE CERTIFICATE

(Taking over)

January 07, 2019

No. 220/UHC/Admin.A/2019--CERTIFIED that the charge of Office of the Registrar (Computer), High Court of Uttarakhand, Nainital, has been taken over by the undersigned in the forenoon of January 04, 2019 after availing earned leave for 02 days *w.e.f.* 02.01.2019 to 03.01.2019 with permission to prefix 26.12.2018 to 01.01.2019 as holidays, which has been sanctioned vide letter No. 6055/XIV-a/41/Admin.A/2013, dated 20.12.2018.

MANOJ GARBYAL,

Registrar (Computer),

U.H.C. Nainital.

Countersigned

(Illegible)

Registrar General

High Court of Uttarakhand, Nainital.

CHARGE CERTIFICATE

(Handing over)

January 07, 2019

No. 221/UHC/Admin.A/2019--CERTIFIED that the charge of Office of the Registrar (Computer), High Court of Uttarakhand, Nainital has been handed over by the undersigned in the afternoon of December 26, 2018 for availing earned leave for 02 days w.e.f. 02.01.2019 to 03.01.2019 with permission to prefix 26.12.2018 to 01.01.2019 as holidays, which has been sanctioned vide letter No. 6055/XIV-a/41/Admin.A/2013, dated 20.12.2018.

MANOJ GARBYAL,

Registrar (Computer),

U.H.C. Nainital.

Countersigned

(Illegible)

Registrar General

High Court of Uttarakhand, Nainital.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

January 07, 2019

No. 11/UHC/Admin.A/2019--In exercise of powers conferred U/S 11 (3) of the Code of Criminal Procedure 1973, following Judicial Officers of the rank of Civil Judge (Jr. Div.) are conferred with the powers of Judicial Magistrate 1st Class to exercise these powers within the district where they remain posted:-

S. No.	Name
1.	Sri Bhupendra Singh Shah
2.	Ms. Minakshi Dubey
3.	Ms. Bhawna Pandey
4.	Sri Vivek Singh Rana
5.	Ms. Shikha Bhandari
6.	Sri Rizwan Ansari
7.	Ms. Kanchan Chaudhary
8.	Ms. Shalini Dadar
9.	Ms. Nisha Devi
10.	Ms. Shivani Nahar
11.	Sri Rohit Joshi
12.	Sri Shambhu Nath Singh Sethwal
13.	Sri Laval Kumar Verma
14.	Sri Kuldeep Narayan
15.	Sri Anil Kumar Kori

By Order of the Court,

Sd/-

PRADEEP PANT,

Registrar General.

CHARGE CERTIFICATE

(Taking over)

January 10, 2019

No. 354/Admin.(A)-UHC/2019--CERTIFIED that, consequent upon Notification No. 01/UHC/Admin.(A)/2016, dated 3rd January, 2019, charge of the Office of the Principal Private Secretary, High Court of Uttarakhand, Nainital, has been taken over by me in the forenoon of 3rd January, 2019.

GURPREET SINGH,

Relieving Officer.

Counter-signed
(PRADEEP PANT)

Registrar General
High Court of Uttarakhand, Nainital.

UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

January 22, 2019

UERC (Guidelines for Appointment of Members and Procedure to be followed by the Forum for Redressal of Grievances of the Consumers) Regulations, 2019

No. F-9(30)/RG/UERC/2019/1507 - In exercise of the powers conferred on it by sub-section (2) (r) of Section 181 read with sub-section (5) of Section 42 of the Electricity Act 2003, and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission hereby frames the "Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (Guidelines for Appointment of Members and Procedure to be followed by the Forum for Redressal of Grievances of the Consumers) Regulations, 2019", as follows:

CHAPTER 1: Preliminary

1.1. Short Title, Applicability, Commencement and Interpretation

- (1) These Regulations may be called the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (Guidelines for Appointment of Members and Procedure to be followed by the Forum for Redressal of Grievances of the Consumers) Regulations, 2019.
- (2) These Regulations extend to the whole of the State of Uttarakhand.
- (3) These Regulations shall be applicable to the Distribution Licensee(s) in the territory of Uttarakhand in their respective licensed areas.

- (4) These Regulations shall come into force on the date of their publication in the official Gazette replacing and repealing "Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (Guidelines for Appointment of Members and Procedure to be followed by the Forum for Redressal of Grievances of the Consumers) Regulations, 2007" and subsequent amendment thereof.
- (5) Words and expression used and not defined in these Regulations but defined in the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) shall have the meanings assigned to them in the said Act.

1.2. Definitions:

- (1) In these Regulations, unless the context otherwise requires: -
- (a) "Act" means the Electricity Act, 2003;
- (b) "Commission" means the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission.
- (c) "Complainant" shall include—
- (i) A consumer as defined under subsection (15) of section 2 of the Act;
- (ii) An applicant for new connections;
- (iii) in case of death of a consumer, his legal heir(s) or authorised representative;
- (iv) An authorised representative;
- (v) Any consumer association registered under the Societies Registration Act, 1860 or under any other law for the time being in force; or
- (vi) Any unregistered association of consumers, where the consumers have similar interest;
- (d) "Complaint" means a letter or application filed with the Forum seeking redressal of grievances concerning the supply of electricity, new connection or the services rendered by the Distribution Licensee(s), including alteration in load/demand, meter related matters, bill related issues and cases where licensee(s) has charged price in excess of the price fixed by the Commission or has recovered the expenses incurred in excess of charges approved by the Commission in providing any electric line or electric plant or has failed to provide compensation to the consumer defined under the UERC (Standard of Performance) Regulations;
- (e) "Distribution Licensee" means a licensee authorised to operate and maintain a distribution system for supplying electricity to the consumers in the concerned area of supply;

- (f) "Forum" means Forum for redressal of grievances of the consumers to be established by distribution licensee in terms of sub-section (5) of section 42 of the Act read with these Regulations;
- (g) "Officer of the licensee" means any person who is appointed by the Distribution Licensee either on full time or part time basis for managing the affairs of the Distribution Licensee and/or carrying out any function under the provisions of the Act for which the Distribution Licensee pays him salary or wages or honorarium or sitting fee or remuneration in any other form.

CHAPTER 2: Constitution and Functions of the Forum

2.1 Constitution of the Forum

- (1) In terms of subsection (5) of Section 42 of the Act, the Distribution Licensee shall establish one or more Forum as may be prescribed by the Commission for redressal of grievances of the consumers in accordance with these Regulations.
- (2) Each Forum shall consist of three members to be appointed by the Distribution Licensee, through proper advertisement in the press and website, after prior approval of the Commission.
- (3) The Distribution Licensee shall from time to time give publicity of the constitution and existence of the Forum in such other manner as the Commission may from time to time lay down including in the electricity bills of the consumers. The names, designation and phone numbers of the members and the concerned officers of the Forum, the address, e-mail, facsimile and phone numbers of the office of the Forum shall be displayed at all the offices of the Distribution Licensee and shall also be duly publicised including on the bills raised on the Consumers.
- (4) The Forum shall have sittings at such Principal office and also at any other place in each district in the area of supply of the Distribution Licensee as may be decided by the Forum from time to time or as the Commission may direct from time to time considering the number of complaints received, the place from where the complaints are received and the proximity to the principal place of business of the Distribution Licensee and other relevant factors.

2.2 Qualification for appointment of Members of the Forum

- (1) Judicial member of the Forum shall be a retired district judge/additional district judge or a retired judicial officer having at least 20 years of experience in legal/judicial profession or a retired civil servant not below the rank of a district collector.
- (2) Technical member shall be a retired officer of any Distribution Licensee company not below the rank of Superintending Engineer possessing degree in Electrical/Mechanical/Electronics/Computer Engineering and having at least 15 years experience in matters relating to the distribution of electricity or a retired Professor of the Electrical Engineering Department of any Government Engineering College or a serving officer of the Distribution Licensee not below the rank of Superintending Engineer serving the area falling within the jurisdiction of the Forum where such member is required.
- (3) Consumer member shall be nominated by the Commission and shall be a person of stature and repute having sufficient exposure to and experience of issues pertaining to consumers of electricity.
- (4) Any person, who has earlier served the position as a full time member and completed his tenure in a Forum, shall be eligible to apply in the same or other Forum, established under the same Distribution Licensee, only after a gap of two years from the date of completion of his tenure.

2.3 Quorum

- (1) Any two member of the Forum appointed under regulation 2.2 of these Regulations shall form the quorum for Forum's sitting.
- (2) The Commission may direct the Distribution Licensee to substitute a member of the Forum with another person as per the composition and qualification provided in regulation 2.2 of these Regulations, if in the opinion of the Commission such substitution is necessary for the proper or effective redressal of the grievances of the Consumers.
- (3) In case where the quorum could not be achieved due to vacancy in the position of members or due to any other reason, leading to non-functioning of the Forum, the Commission may, on being informed by the Distribution Licensee, transfer the charge of such Forum to a Forum of neighboring jurisdiction for dealing with the complaints of the consumers.

2.4 Term of Office and Conditions of Service

- (1) Members of the Forum shall hold office for a term of three years which may be extendable upto two years. The upper age limit for the appointment of the member shall be 65 years and can hold the office only upto the age of 68 years.
- (2) The Distribution Licensee shall ensure that no post of a member in the Forum remains vacant for a period exceeding 30 days.
- (3) The salary, sitting fees, honorarium and/or other allowances (collectively called "Remuneration") payable to all the members appointed under regulation 2.2 of these Regulations including their terms of appointment shall be uniform and such as may be prescribed by the Commission from time to time.
- (4) The Judicial and Consumer member shall be appointed as full time members and Judicial member shall be administrative head of the Forum.
- (5) Notwithstanding the foregoing provisions of sub-regulation (1) to (4) of regulations 2.4 of these Regulations, the terms and conditions of service of a member in the Forum who is in the employment of the Distribution Licensee shall be governed by the terms and conditions of his employment with such Distribution Licensee.

2.5 Disqualification/ Removal of Member

- (1) No person shall be appointed and/or be entitled to continue as a member if he stands disqualified on account of his:
 - (a) having been adjudged as an insolvent;
 - (b) having been convicted of an offence, involving moral turpitude;

- (c) having become physically or mentally incapable of acting as such member;
 - (d) having acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a member;
 - (e) having so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest; or
 - (f) having been guilty of misbehavior;
 - (g) having been guilty of action(s) inconsistent with norms of conduct expected of any judicial or quasi judicial functionary.
- (2) An existing member shall be liable to be removed from his office forthwith in the event of any of the disqualifications provided at sub-regulation (1) of regulation 2.5 of these Regulations arising or being discovered.

Provided that no full time member shall be removed from his office on any ground specified in sub-regulation (1) of regulation 2.5 of these Regulations unless the Distribution Licensee, has, on an inquiry held by it, concluded that such member ought, on such ground or grounds, be removed.

Provided further that the decision of removal of the member shall be subject to approval of the Commission.

- (3) Where the Commission is dissatisfied with the functioning of any/all member(s) of a Forum and is of the opinion that such removal is necessary in the interest of consumers and effective redressal of their grievances, the Commission may, after giving an opportunity to such member(s), direct the Distribution Licensee to remove the member(s) of the Forum.

2.6 Infrastructure facilities

- (1) For efficient functioning of the Forum, the Distribution Licensee shall provide:
- (a) An office space consisting of three rooms one each for the three members, a hearing hall/room, one record room and one common room for the secretarial staff.
 - (b) Computers and other facilities required by the members/secretarial staff.

Provided that all costs prudently incurred by a Distribution Licensee on the establishment and running of the Forum, to the extent reasonable and justifiable, shall be allowed in the determination of tariff of the Distribution Licensee in accordance with the Regulations of the Commission.

CHAPTER 3: Jurisdiction and Proceedings of the Forum

3.1 Jurisdiction of the Forum

- (1) The Forum shall have the jurisdiction to entertain the grievances filed by the complainant with respect to the services provided by the Distribution Licensee and give such orders and directions as may be deemed necessary.
- (2) The Forum shall entertain only those complaints which fall under sub-regulation (1) (d) of regulation 1.2 of these Regulations.
- (3) The Forum shall not entertain a grievance if it pertains to the same subject matter for which any proceedings before any court, authority or any other Forum is pending or a decree, award or a final order has already been passed by any competent court, authority or forum.
- (4) The Forum shall not entertain grievances falling under Sections 126, 127, 135 to 140 and 161 of the Act and matter relating to recovery of arrears where bill amount is not disputed.
- (5) The Forum shall not entertain any grievances pertaining to shifting of electric lines/poles/equipments.
- (6) Subject to sub-regulation (3), (4) and (5) of regulation 3.1 of these Regulations, no grievance shall be rejected by the Forum at any stage, unless the complainant has been given an opportunity of being heard.

3.2 Complaints at the Forum

- (1) The Forum shall receive the complaints of consumers forwarded or filed with the Forum so long as such complaints are in writing and the Forum shall not insist on or prescribe any specific format for filing of complaints or for entertaining them.
- (2) The office of the Forum shall issue acknowledgment of the receipt of the Complaint to the Complainant showing clearly the date of receipt of Complaint and carrying seal of the Forum. No complaint shall be returned to the Complainant without issuing acknowledgement of its receipt and the same shall be disposed off according to the law.
- (3) The Forum shall maintain true and correct records of all Complaints received by the Forum from time to time and make available such records for inspection as the Commission may require from time to time.
- (4) In any hearing, the Distribution Licensee, shall not be represented by professional counsel, attorney or advocate, unless the Forum so permits. However, where the consumer chooses to be represented by counsel, attorney or advocate, then the Distribution Licensee shall be granted a similar privilege.

3.3 Grievance Handling Procedure of the Forum

- (1) The Forum shall decide the Complaints received expeditiously and shall communicate its decision to the Complainant within a period not exceeding 60 days of the receipt of the Complaint. The Forum shall give the reasons in support of its decisions.
- (2) If a member hearing the matter does not agree with the decision taken by other members, he may record his note of dissent with reasons but the decision taken by majority of members hearing the case will prevail.
- (3) All decisions of the Forum shall strictly be in accordance with the provisions of the Act, Rules and Regulations framed thereunder and orders and directions issued by the Commission from time to time.
- (4) Where the Forum is satisfied that any of the allegations contained in the grievance is correct, it shall issue an order to the Distribution Licensee directing it to do one or more of the following things in a time bound manner, namely-
 - (a) to return to the applicant the undue charges paid by it;
 - (b) to pay such amount as may be awarded by it as compensation to the applicant, provided however that in no case shall any consumer be entitled to indirect, consequential, incidental, or punitive damages, loss of profits or opportunity, whether arising in contract, tort, warranty, strict liability or any legal theory;
 - (c) to remove the cause of grievance in question;
 - (d) to comply with the order within stipulated time;
 - (e) to give a compliance report within the time limit specified in these regulations;
 - (f) to apprise the aggrieved person of the things he is required to do along with time limits, for compliance of the order;
 - (g) any other order deemed appropriate in the facts and circumstances of the case.
- (5) The Forum, after considering all submissions written or oral made before it by complainant or Distribution Licensee, shall pass speaking orders giving the reasons in support of its decisions. Every order passed by the Forum shall be signed by all the members deciding the case.
- (6) Certified copies of every order passed by the Forum shall be delivered to the parties within 3 days of the order.
- (7) The order of the Forum shall be binding on the aggrieved person and the Distribution Licensee.

- (8) The Forum shall specify the period for compliance by Distribution Licensee or the consumer as the case may be. Normally this period should be 30 days. In case, compliance of the order involves major work/scope to be done, this period of 30 days may be extended with the reasons to be recorded in writing.
- (9) The Distribution Licensee and the applicant shall comply with the order diligently and within the timeframe as specified in the order and report compliance to Forum within 7 days of the implementation of the order.
- (10) In case of delay in compliance beyond the time limit stipulated by the Forum in its order, the applicant or the Distribution Licensee as the case may be, shall file the reasons for delay on its part within 7 days of the stipulated date and give the likely date by which compliance shall be made.
- (11) The Forum may take appropriate action, if deemed fit, for any delay in implementation of its order or in filing of the compliance report by the Distribution Licensee.
- (12) Non-compliance of Forum's order by either party shall be in violation of these Regulations and shall be liable for appropriate remedial action against it under Section 142 and 146 read with Section 149 of the Electricity Act, 2003.
- (13) All orders issued by the Forum shall be forwarded to the Distribution Licensee who shall, on receiving these orders, upload the same on its official website.

3.4 Submissions of Reports to the Commission

- (1) The Forum shall submit a quarterly report to the Commission on the number of complaints received, redressed and pending, within 15 days of the end of the quarter, along with reasons for their pendency.
- (2) The Forum shall also furnish to the commission, by 31st March every year, a report containing a general review of the activities of their offices during the preceding financial year and shall furnish such information as the Commission may require.

3.5 Inspection of Records and Supply of Certified Copies

- (1) The aggrieved person and the Distribution Licensee shall be entitled to obtain certified copies of the orders, decisions, directions and reasons in support thereof given by the Forum in respect of the grievance.
- (2) Any person shall be entitled to a copy of the documents or orders of the Forum subject to payment of fee and complying with other terms, which the Forum may direct.

3.6 Appeal before Ombudsman

Any consumer aggrieved by the order of the Forum or non-disposal of his complaint by the Forum within the specified time limit may prefer an appeal to the Ombudsman appointed by the Commission under the Act, in such form and manner, as may be laid down in the Regulations of the Commission.

3.7 Commissions power of Superintendence

- (1) The Commission shall have the general powers of superintendence and control over the Forum and for this purpose may call for any record from the Forum/Distribution Licensee and pass appropriate orders thereupon. The Forum/Distribution Licensee shall duly comply with such directions as the Commission may issue from time to time.
- (2) Subject to the provisions of the Act, the Commission may from time to time issue orders and practice directions in regard to the implementation of these Regulations.

CHAPTER 4: General

4.1 Savings

Nothing contained in these regulations shall affect the rights and privileges of the consumer under any other law for the time being in force, including under the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986) and amendments issued from time to time.

4.2 Powers to Remove Difficulties

If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these Regulations, the Commission may by general or special order, direct the Distribution Licensee, the Forum to take suitable action, not being inconsistent with the Electricity Act, 2003, which appears to the Commission to be necessary or expedient for the purpose of removing difficulties.

4.3 Power to Amend

The Commission may, at any time add, vary, alter, modify or amend any provision of these Regulations.

By order of the Commission,

NEERAJ SATI,

Secretary,

Uttarakhand Electricity Regulatory Commission.

कार्यालय राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड

(विधि-अनुभाग)

03 जनवरी, 2019 ई०

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य०), राज्य कर,

देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/रुद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक 7602/रा०कर आयु० उत्तरा०/रा०क०मु०/विधि-अनुभाग/18-19/देहरादून-आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड द्वारा जारी अधिसूचना संख्याएं 7545/सी०एस०टी०यू०के०/जी०एस०टी०-विधि/2018-19/CT-68; 7546/सी०एस०टी०यू०के०/जी०एस०टी०-विधि/2018-19/CT-69 एवं 7547/सी०एस०टी०यू०के०/जी०एस०टी०-विधि/2018-19/CT-68 समदिनांकित 31 दिसम्बर, 2018 का संदर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड द्वारा जारी अधिसूचना संख्याएं 3905 दिनांक 15 नवम्बर, 2018; 6237(I) दिनांक 23 मार्च, 2018 एवं अधिसूचना संख्या 5525 दिनांक 26 अक्टूबर, 2018 में अग्रेतर संशोधन किया जाना अधिसूचित किया गया है।

उक्त अधिसूचनाओं की प्रति इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त अधिसूचनाओं की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर-निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड

31 दिसम्बर, 2018 ई0

संख्या 7545/सी0एस0टी0यू0के0/जी0एस0टी0-विधि/2018-19/CT-68-उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम (5) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के साथ पठित उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, मैं आयुक्त :-

- (i) अधिसूचना संख्या 4563/सी0एस0टी0यू0के0/जी0एस0टी0-विधि/2018-19/CT-45 दिनांक 13 सितम्बर, 2018 के द्वारा यथा संशोधित अधिसूचना संख्या 2319/सी0एस0टी0यू0के0/जी0एस0टी0-विधि/2017-18 दिनांक 08 अगस्त, 2017 में; और
- (ii) अधिसूचना संख्या 4563/सी0एस0टी0यू0के0/जी0एस0टी0-विधि/2018-19/CT-45 दिनांक 13 सितम्बर, 2018 के द्वारा यथा संशोधित अधिसूचना संख्या 3905/सी0एस0टी0यू0के0/जी0एस0टी0-विधि/2017-18 दिनांक 15 नवम्बर, 2017 में; निम्नलिखित अग्रेतर संशोधन करती हूँ, अर्थात्-

उक्त अधिसूचनाओं के पहले पैरा के परन्तुक में "जुलाई, 2017 से नवम्बर 2018" और "31 दिसम्बर, 2018" शब्दों, अंकों के स्थान पर क्रमशः "जुलाई, 2017 से फरवरी, 2019" और "31 मार्च, 2019" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

NOTIFICATION

December 31, 2018

No. 7545/CSTUK/GST-Vidhi Section/2018-19/CT-68-In exercise of the powers conferred by section 168 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, I, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments-

- (i) in notification No. 2319/CSTUK/GST-Vidhi Section/2017-18 dated the 08th August, 2017 as amended vide notification No. 4563/CSTUK/GST-Vidhi Section/2018-19/CT-45 dated the 13th September, 2018; and
- (ii) in notification No. 3905/CSTUK/GST-Vidhi Section/2017-18 dated the 15th November, 2017 as amended vide notification No. 4563/CSTUK/GST-Vidhi Section/2018-19/CT-45 dated the 13th September, 2018; namely :-

In the said notifications, in the first paragraph in the proviso, for the words, figures and letters "July, 2017 to November, 2018" and "31st day of December, 2018", the words, figures and letters "July, 2017 to February, 2019" and "31st day of March, 2019" shall be respectively substituted.

31 दिसम्बर, 2018 ई०

संख्या 7546/सी०एस०टी०यू०के०/जी०एस०टी०-विधि/2018-19/CT-69-उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम (5) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के साथ पठित उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, मैं आयुक्त :-

- (i) अधिसूचना संख्या 4566/सी०एस०टी०यू०के०/जी०एस०टी०-विधि/2018-19/CT-46 दिनांक 13 सितम्बर, 2018 के द्वारा यथा संशोधित अधिसूचना संख्या 3795/सी०एस०टी०यू०के०/जी०एस०टी०-विधि/2017-18 दिनांक 06 नवम्बर, 2017 में; और
- (ii) अधिसूचना संख्या 4566/सी०एस०टी०यू०के०/जी०एस०टी०-विधि/2018-19/CT-46 दिनांक 13 सितम्बर, 2018 के द्वारा यथा संशोधित अधिसूचना संख्या 6237(i)/सी०एस०टी०यू०के०/जी०एस०टी०-विधि/2017-18 दिनांक 23 मार्च, 2018 में;

निम्नलिखित अगेतर संशोधन करती हूँ, अर्थात्-

उक्त अधिसूचनाओं के पहले पैरा के परन्तुक में "जुलाई, 2017 से नवम्बर 2018" और "31 दिसम्बर, 2018" शब्दों और अंकों के स्थान पर क्रमशः "जुलाई, 2017 से फरवरी, 2019" और "31 मार्च, 2019" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

NOTIFICATION

December 31, 2018

No. 7546/CSTUK/GST-Vidhi Section/2018-19/CT-69-In exercise of the powers conferred by section 168 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, I, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments-

- (i) in notification No. 3795/CSTUK/GST-Vidhi Section/2017-18 dated the 06th November, 2017 as amended vide notification No. 4566/CSTUK/GST-Vidhi Section/2018-19/CT-46 dated the 13th September, 2018; and
- (ii) in notification No. 6237(i)/CSTUK/GST-Vidhi Section/2017-18 dated the 23rd March, 2018 as amended vide notification No. 4566/CSTUK/GST-Vidhi Section/2018-19/CT-46 dated the 13th September, 2018; namely :-

In the said notifications, in the first paragraph, in the proviso, for the words, figures and letters "July, 2017 to November, 2018" and "31st day of December, 2018", the words, figures and letters "July, 2017 to February, 2019" and "31st day of March, 2019" shall be respectively substituted.

31 दिसम्बर, 2018 ई०

संख्या 7547/सी०एस०टी०यू०के०/जी०एस०टी०-विधि/2018-19/CT-70-उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम (5) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के साथ पठित उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, मैं आयुक्त, अधिसूचना संख्या 4207/सी०एस०टी०यू०के०/जी०एस०टी०-विधि/2018-19/CT-35 दिनांक 27 अगस्त, 2018, अधिसूचना संख्या 4567/सी०एस०टी०यू०के०/जी०एस०टी०-विधि/2018-19/CT-47 दिनांक 13 सितम्बर, 2018 और अधिसूचना संख्या 5525/सी०एस०टी०यू०के०/जी०एस०टी०-विधि/2018-19/CT-55 दिनांक 26 अक्टूबर, 2018 के द्वारा यथा संशोधित अधिसूचना संख्या 3043/सी०एस०टी०यू०के०/जी०एस०टी०-विधि/2018-19 दिनांक 10 अगस्त, 2018 में निम्नलिखित अग्रेतर संशोधन करती हूँ, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना के पहले पैरा में अधिसूचना संख्या 4567/सी०एस०टी०यू०के०/जी०एस०टी०-विधि/2018-19/CT-47 दिनांक 13 सितम्बर, 2018 के द्वारा अन्तःस्थापित परन्तुक में "जुलाई, 2017 से नवम्बर 2018" और "31 दिसम्बर, 2018" शब्दों और अंकों के स्थान पर क्रमशः "जुलाई, 2017 से फरवरी, 2019" और "31 मार्च, 2019" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

सौजन्या,
आयुक्त राज्य कर,
उत्तराखण्ड।

NOTIFICATION

December 31, 2018

No. 7547/CSTUK/GST-Vidhi Section/2018-19/CT-70—In exercise of the powers conferred by section 168 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, I, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in notification No. 3043/CSTUK/GST-Vidhi Section/2018-19 dated the 10th August, 2018 as amended vide notification No. 4207/CSTUK/GST-Vidhi Section/2018-19/CT-35 dated the 27th August, 2018, notification No. 4567/CSTUK/GST-Vidhi Section/2018-19/CT-47 dated the 13th September, 2018 and notification No. 5525/CSTUK/GST-Vidhi Section/2018-19/CT-55 dated the 26th October, 2018; namely :-

In the said notifications, in the first paragraph, in the proviso inserted vide notification No. 4567/CSTUK/GST-Vidhi Section/2018-19/CT-47 dated the 13th September, 2018; for the words, figures and letters "July, 2017 to November, 2018" and "31st day of December, 2018", the words, figures and letters "July, 2017 to February, 2019" and "31st day of March, 2019" shall be respectively substituted.

SOWJANYA,
Commissioner State Tax,
Uttarakhand.

विपिन चन्द्र,
अपर आयुक्त राज्य कर,
मुख्यालय देहरादून।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 05 हिन्दी गजट/81-भाग 1-क-2019 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।